

‘ओम बिड़ला के ओ.एस.डी. राजीव दत्ता पर लगे मानव तस्करी के आरोपों की जाँच गंभीरता और तीव्रता से करें’

राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में दायर एफ.आई.आर. तथा परिवादों की जाँच ए.डी.जी. (अपराध) दिनेश एम.एन. के निरीक्षण में की जाए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4, अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता, अर्चना झाला, दिनेश मुरझानी व वंदिता राणा पुलिस अधीक्षक अजमेर के विरुद्ध अजमेर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग मानव तस्करी की शिकायत का अनुसंधान एडीजी क्राइम दिनेश एम.एन. करेंगे एवं याचिकाकर्ता एडवोकेट शेखर मेवाड़ा के विरुद्ध दर्ज एफआईआर का अनुसंधान भी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ही करेंगे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से

- अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को कानूनी सुरक्षा देते हुए कहा कि इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बलपूर्वक या दण्डात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता, जैसे कि उनकी गिरफ्तारी करना इत्यादि, जब तक अदालत ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती या याचिकाकर्ता जाँच में सहयोग नहीं करते।
- याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवार दायर किया है, परन्तु कोटा में राजनैतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जिसकी भी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवार दायर की है, परन्तु कोटा में राजनैतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके

साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जिसकी भी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। अधिवक्ता शेखर मेवाड़ा पर बूंदी में हुए कतिलाना हमले की एफआईआर

दर्ज करने के निर्देश दिए एवं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता एवं रविंदर गौड़ (आईजी कोटा), गंगा सहाय (डिप्टी एसपी कोटा सिटी), राजेन्द्र कुमार मीणा (एसपी बूंदी), रमेश आर्य (एसएचओ सदर बूंदी), सुनील खटाना व अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश दिया।

निम्न याचिकाओं की तरफ से अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य ने न्यायालय को बताया कि ऊपर बताए गए व्यक्तियों के खिलाफ मानव तस्करी में परिवार अनुसंधान में लंबित है तथा उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश के अनुसार, “पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय में उपस्थित अधिकारी (दिनेश एम.एन.) द्वारा दी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्कूल इमारतों की बर्दहाल स्थिति पर सरकार दो सप्ताह में जवाब दे

जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की स्कूलों की इमारतों की बर्दहाल स्थिति और उनमें संसाधनों के अभाव से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सहित अन्य वकील पेश हुए। उन्होंने अदालत

- हाई कोर्ट ने प्रकरण के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान की सुनवाई 18 अगस्त को तय की।

से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 जुलाई को प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों सहित उनमें संसाधनों की कमी को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव, एसएस शिक्षा, प्रमुख बाल कल्याण सचिव और राष्ट्रीय बाल आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की एक अन्य एकलपीठ ने स्कूल भवनों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है केन्द्र सरकार?

दिन भर सोशल मीडिया पर यह चर्चा आम रही

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 अगस्त। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बात को लेकर एक खास हलचल देखी जा रही है कि केन्द्र सरकार अनुच्छेद 370 हटाय जाने की छठी वर्षगांठ, यानी 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है।

याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके, जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, में बांट दिया था। इसके साथ ही, राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी तथा वहां की सत्ता एक उप-राज्यपाल के अधीन कर दी गई थी।

केन्द्र पर कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने का दबाव भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में केन्द्र सरकार से राज्य का दर्जा जल्द से जल्द तथा “यथाशीघ्र” बहाल करने को कहा था। करीब दस साल के लम्बे इन्तज़ार के बाद, पिछले साल यहां विधानसभा चुनाव हुए, जिसके बाद मध्यमंजरी उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता लगातार राज्य का दर्जा

- चर्चा है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठा सकती है।
- लेकिन, यह भी कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार को भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों का इस पर समर्थन शायद ना मिले।
- भाजपा व मोदी के कई समर्थकों ने कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर चिंता जताई और कहा, जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की गलती न की जाए।

बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हाल के कुछ घटनाक्रमों ने राज्य के दर्जे की लम्बित बहाली की इन अफवाहों को और बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से भेंट की। शाह ने जम्मू-कश्मीर के कुछ नेताओं और भाजपा के प्रदेश प्रमुख के साथ भी मीटिंग की। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एनडीए सांसदों की भी बैठक बुलाई है। अगर वाकई राज्य का दर्जा बहाल होता है, तो यह कदम प्रधानमंत्री मोदी को वर्तमान गम्भीर चुनौतियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इसके अलावा, पहलाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान पर की गई सैन्य कार्रवाई से भी भारत की कूटनीतिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों में भारत सरकार की स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह कदम भाजपा के समर्थकों को शायद पसंद न आए। सेना के पूर्व अधिकारी और लेखक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने के साथ ही नसीहत भी दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर दिए गए बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी, साथ ही यह सवाल भी उठाया कि उन्होंने यह मुद्दा सोशल मीडिया पर क्यों उठाया, संसद में क्यों नहीं?

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहुल गांधी को सावधान करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे सोशल मीडिया पर उठाने की बजाय संसद में उठाए जाने चाहिए। बेंच ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में विचारधीन उस क्रिमिनल मानहानि केस में स्टे दे दिया, जो 2022 की “भारत जोड़ो यात्रा” के दौरान भारतीय सेना के बारे में की गई उनकी टिप्पणी

- सुप्रीम कोर्ट ने सेना के कथित अपमान संबंधी एक केस, जो लखनऊ की एक अदालत में चल रहा था, में कार्यवाही पर स्टे लगा दिया।
- राहुल पर आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी कि चीन के सैनिक अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पीट रहे थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर राहत दी कि राहुल की टिप्पणी से शिकायतकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है।
- कोर्ट ने यह भी कहा, यह मुद्दा संसद में उठाया जाना चाहिए।

से सम्बंधित है। गांधी ने कहा था कि “चीनी सैनिक अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं।” यह टिप्पणी “लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल” पर चीनी कार्यवाही को लेकर, केन्द्र सरकार को निशाना बनाते हुये की गई थी। अदालत ने गांधी से यह भी पूछा

कि क्या उनकी टिप्पणी किसी विश्वसनीय सामग्री पर आधारित थी। बेंच ने कहा, “आपने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर क्यों की? संसद में क्यों नहीं? आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? आपके पास इसका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पेपर लीक में याचिकाकर्ता की बहस पूरी हुई

जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ता पक्ष से जुड़े सभी वकीलों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए पांच अगस्त का समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से ओपी

- अब सुनवाई 5 अगस्त को।

सोलंकी और हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती को रद्द करने की गुहार करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में भर्ती को लेकर राज्य सरकार कोई निर्णय ले, ऐसी प्रार्थना नहीं की गई है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी करने के बाद अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त को तय की है।

क्या बिहार चुनाव के बाद कोई बम फोड़ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू?

लगातार दूसरी बार मोदी सरकार की नीतियों पर विरोध जताया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 अगस्त। एक ऐसे कदम के अन्तर्गत, जो एनडीए गठबंधन में दरार को और गहरा कर सकता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने केन्द्र सरकार को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने चिंता जताई है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई टैरिफ वृद्धि का आंध्र प्रदेश के झींगा (श्रिम्प) और मत्स्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मोदी सरकार को संबोधित इस पत्र में तटीय क्षेत्रों के उन किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, जो समुद्री खाद्य निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हैं।

नायडू का यह पत्र ऐसे समय में आया है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के इस कदम पर अब तक चुपची साध रखी है, जबकि यह भारत के जलीय कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से झींगा

- अब चंद्रबाबू नायडू ने ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार को कड़ा पत्र लिखा व आंध्र के मत्स्य उद्योग के लिए गंभीर चिंता जताई।
- इससे पहले चंद्रबाबू ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर नाराज़गी जताई थी।
- नायडू के इन कदमों को एनडीए में दरार पड़ने का पूर्व संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा, अगर बिहार चुनाव के नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं आए तो नायडू कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।

निर्यात में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, के लिए गंभीर आर्थिक नतीजों का कारण बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह घटनाक्रम टीडीपी और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के बीच बढ़ते अंतर्घर्ष का एक और संकेत है। हाल के हफ्तों में यह दूसरा अवसर है, जब नायडू ने खुलकर असहमति जताई है। इससे पहले, नायडू ने बिहार में

केन्द्र की विवादस्पद विशेष मतदाता पुनरीक्षण पहल को लेकर नाराज़गी जताई थी। विपक्ष ने भी तीखे शब्दों में विशेष मतदाता पुनरीक्षण की आलोचना की थी तथा इसे, चुनाव से ठीक पहले, एक संवेदनशील राज्य में मतदाता सूची से छेड़छाड़ का प्रयास बताया था। पिछले एक महीने में, नायडू ने कम से कम छह प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चिंता जताई है, जो संकेत देता है कि एक समय

मजबूत रहा एनडीए का गठबंधन अब ढीला हो रहा है। नायडू की यह सतर्क, लेकिन रणनीतिक स्थिति भाजपा एवं विपक्ष दोनों के लिये ही इस बात का संकेत मानी जा रही है कि टीडीपी भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर नए विकल्पों पर विचार कर रही हो सकती है। आंध्र के मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों का कहना है कि नायडू “राजनीतिक हालात” पर गहराई से नजर रखे हुए हैं, खासकर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर। एक शीघ्र टीडीपी पदाधिकारी ने इस संवाददाता को पुष्टि की कि “नायडू, बिहार चुनाव परिणामों के बाद ही, मोदी सरकार को भविष्य में समर्थन देते रहने के बारे में स्पष्ट रुख अपनाएंगी।” राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नायडू के हालिया कदम एनडीए के क्षेत्रीय सहयोगियों में बढ़ती स्वायत्तता की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। हैदराबाद के एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘रुस से तेल खरीदा तो आयात शुल्क और बढ़ायेंगे’

वाशिंगटन, 04 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी है कि यदि भारत ने रुस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वह भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क और बढ़ा देंगे। ट्रंप ने टुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत को इस बात की चिंता नहीं है कि यूक्रेन में रुस कितने लोगों को मार रहा है। इस कारण, “मैं भारत द्वारा

- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने फिर भारत को धमकी दी।
- अमेरिका को दिये जाने वाले आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी करूँगा।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ रुस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि उसमें से ज्यादातर तेल खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने 01 अगस्त से दुनिया के कई देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप की टैरिफ धमकी के जवाब में स्वदेशी का नारा दिया प्र.मंत्री मोदी ने

प्र.मंत्री ने एक रैली में कहा, हम वो सामान खरीदेंगे, जो एक भारतीय के पसीने से बना हो

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4, अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक चुनौतीपूर्ण रुख अपनाते हुए, देशवासियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की और संकेत दिया कि भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखेगा। जानकारी सूत्रों ने ब्लूमबर्ग को बताया, भारत सरकार ने देश की तेल रिफाइनरियों को रूसी तेल की खरीद रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया है और इस बारे में कोई अंतिम निर्णय भी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की रिफाइनरियों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्रोत चुनने की अनुमति है और

कच्चे तेल की खरीद एक व्यावसायिक निर्णय बना हुआ है। सप्ताहांत में पीएम मोदी ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार ने भारत के निर्यातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है और भारत की खरीद जारी रखता है तो और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा था, विश्व अर्थव्यवस्था अनेक आशंकाओं से गुजर रही है, एक अस्थिरता का माहौल है, “अब जो भी हम खरीदें, एक ही कसौटी होनी चाहिए, हम वही चीजें

- ट्रंप की टैरिफ धमकी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया और निर्देश दिए कि रुस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी जाएगी।
- यूक्रेन युद्ध रोकने पर पुतिन के इन्कार के बाद ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा और कहा कि भारत रुस से जो तेल खरीद रहा है उसी आय से रुस युद्ध कर रहा है।
- हालांकि, चीन भी रुस से बराबर तेल खरीद रहा है, पर, विश्व की इस दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से टकराने की हिम्मत शायद अमेरिका में नहीं है। इसलिए अमेरिका व उसके समर्थक देश भारत पर निशाना साध रहे हैं।
- चूंकि, भारत एक बहुत बड़ा कन्ज्यूमर बेस है, इसलिए सवाल यह है कि इतने बड़े उपभोक्ता बाज़ार की अनदेखी कर अमेरिका, भारत पर टैरिफ कब तक जारी रखेगा?

खरीदेंगे, जो एक भारतीय के पसीने से बनी है।” यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिशों के तहत अमेरिका ने अब भारत को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स सदस्यता और रुस के साथ घनिष्ठ संबंधों को लेकर भारत की तीखी आलोचना की और कहा, “वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर डूब सकते हैं।” यह बात अमेरिका की ओर से एक बड़े रुख परिवर्तन का संकेत है। अमेरिका ने वर्षों तक भारत और रुस के ऐतिहासिक संबंधों को नजरअंदाज करते हुए भारत को एशिया में चीन के मुकाबले संतुलन के रूप में देखा था।

अब राष्ट्रपति ट्रंप इस रणनीति को त्यागते हुए, पुतिन पर दबाव बढ़ाने की राह पर हैं, जिन्होंने युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी कोशिशों का विरोध किया है। वाइट हाउस के उप प्रमुख स्टीफन मिलर ने रविवार को भारत पर भारी टैरिफ लगाने, अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने और रुस से चीन के बराबर तेल खरीदने का आरोप लगाया। मिलर ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री के साथ हमेशा शानदार संबंध चाहते रहे हैं, लेकिन अब हमें युद्ध की फंडिंग के विषय में सच्चाई का सामना करना होगा।” मिलर ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप सभी विकल्पों को खुला रखे हुए हैं, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झारखंड के पूर्व मु.मंत्री शिबू सोरेन का निधन



नयी दिल्ली/रांची, 04 अगस्त। पृथक झारखंड आंदोलन के अग्रदूत एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को यहां निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। सोरेन एक माह से भी अधिक समय से यहां सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती थे। उनका किडनी तथा हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यहां गंगाराम अस्पताल जाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

कृत्रिम सुख की बजाये, हमेशा ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये। –अब्दुल कलाम

एस.आई.आर. पर रार, आर या पार

आजकल बिहार की मतदाता सूचियों का एस आई आर (विशेष गहन पुनरीक्षण यानि स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) चल रहा है। यह पूरे देश में सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार एस आई आर सभी राज्यों के लिए भी किया जाएगा । अत: देशवासियों के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह क्या है और इसका क्या प्रभाव होगा?

चुनाव आयोग के अनुसार एस आई आर, मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिससे मृत, स्थाई रूप से पलायन करने वालों और अयोग्य लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाते हैं। इसमें, पूरी मतदाता सूची नई बनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को नामांकन प्रपत्र भरकर बी एल ओ के पास जमा कराना होता है। बी एल ओ द्वारा इन सबको अपलोड किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार हर उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होगा जो भारत का नागरिक है और 18 साल से ऊपर है। जिस तरह से धरातल पर बिहार में यह कार्य चल रहा है, उसे देखकर, सभी विपक्षी दल एस आई आर को केवल लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया बता रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने प्राप्त प्रपत्रों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूचियां का प्रकाशन 1अगस्त 2025 को कर दिया है। 24 जून 2025 को उपलब्ध मतदाता सूचियों में कुल 7.89 करोड़ नाम अंकित थे जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में कुल 7.24 करोड़ नाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए मतदाता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है ।

प्रश्न यह नहीं है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, वे किस दल के हैं, अपितु यह कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार है या नहीं? यदि कोई भी कार्यवाही उन्हें मताधिकार से वंचित करने का काम कर रही है तो यह बहुत गंभीर बात है । यदि वास्तव में इसके कारण लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित होते हैं तो इसे रोकने की आवश्यकता है।

हम एस आई आर की प्रक्रिया को थोड़ा सिलसिले वार समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्राप्त है, सामान्यतया किसी भी राज्य में या क्षेत्र में वयस्क लोगों की संख्या वहां के मतदाता सूचियों में अंकित संख्या के बराबर होनी चाहिए। देश के अनेक राज्यों में मतदाताओं की संख्या, उस राज्य की अनुमानित वयस्क जनसंख्या से अधिक है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 102%, कर्नाटका में 108%, तेलंगाना में 116%, ओडिशा में 105% और पश्चिम बंगाल में यह 101% है। इनकी तुलना में बिहार में यह 97% है।

इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार यह होता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम एक स्थान पर मतदाता सूची में अंकित है, वह किसी कारणवश दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के समय उसका नाम वहां भी जुड़ जाता है । इस प्रकार उसका नाम दो स्थान पर हो जाता है। व यह यदि पुराने स्थान से नाम कटवाने का प्रार्थना पत्र देता है तो भी उसका नाम नहीं कटता है। मेरा स्वयं का जब 1995 में जयपुर से झूंरापुर स्थानांतरण हुआ तो जयपुर में अपना नाम कटवाने के लिए, जिम्मेदार नागरिक की तरह आवेदन किया, किंतु इसकी कोई पुख्ता सूचना मुझे नहीं मिली। उसके बाद झूंरापुर में कलेक्टर के पद का भार ग्रहण करने के बाद मैंने वहां की मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया और वहां अंकित भी हो गया। यहां मैंने मतदान भी किया। इसके बाद जब मैं जयपुर वापस आया और यहां नाम जुड़वाने का प्रयास किया तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम तो यहां की मतदाता सूची में से काटा ही नहीं गया था। इस प्रकार लगभग एक वर्ष का कम मेरा नाम दो स्थानों पर अंकित रहा। जब यह स्थिति एक आईएसएस अधिकारी के साथ हो सकती है तो पता नहीं कितने अनगिनत व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होगा । नेजस्वी यादव को इसी बात पर तो नोटिस दिया जा रहा है।

अब हम जरा बिहार की ही बात कर लें । 24 जून 2025 को उपलब्ध मतदाता सूची में यह संख्या 7.89 करोड़ थी जबकि अनुमानित वयस्क जनसंख्या बिहार में 8.16 करोड़ थी। जब इस समय राष्ट्रपति का प्रकाशन एक अगस्त 2025 को हुआ है तो अनुमानित वयस्क जनसंख्या 8.18 करोड़ की तुलना में निर्वाचकों की संख्या 7.24 करोड़ है जो कि कुल वयस्क जनसंख्या का 88% है। स्पष्ट है कि बिहार की वयस्क जनसंख्या की तुलना में मतदाताओं की संख्या 94 लाख कम हो गई है।

यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में पंविब है। वहां पर उसकी सुनवाई भी चल रही है। न्यायालय ने कहा है कि एस आर आर की प्रक्रिया, सभी योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए होनी चाहिए न कि लोगों के नाम काटने के लिए । जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग धरातल पर काम कर रहा है, और इसके कई सबूत वीडियो और रिपोर्ट के द्वारा मीडिया में आए हैं, उससे तो यह लगता है कि निर्वाचन आयोग केवल मतदाताओं के नाम काटने के लिए यह काम कर रहा है। 24 जून, 2025 की मतदाता सूचियों में से, ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में 65 लाख लोगों के नाम कम हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि इसमें एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। किसी मतदाता का नाम विदेशी नागरिक होने के आधार भी पर नहीं काटा गया है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से 22 लाख मृतक हैं, 36 लाख ऐसे हैं जो स्थाई रूप से दूसरे स्थान पर चले गए या जिनकी कोई जानकारी नहीं है एवं 7 लाख ऐसे हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थान में अंकित हैं। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने से पूर्व उसकी सुनवाई करना आवश्यक है। ऐसा कुछ भी काम इस बार नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग यह कह रहा है कि जिन लोगों के नाम अंकित नहीं हैं, वे अपनी आपत्ति 31 अगस्त तक दे सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि जिन 7.24 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में उपलब्ध हैं, उनमें से भी अनेक ऐसे हैं जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी एक देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे एवं इसके कारण उनके भी नाम कट जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की संभावित संख्या कुछ भी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार सभी को जोड़कर लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्तियों के नाम बिहार की मतदाता सूचियां से काट दिए जाने की संभावना है। ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के ठीक विपरीत है जिसके अनुसार लक्ष्म समावेश का होना चाहिए न कि अधिकाधिक निष्कासन का।

जिन लोगों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हैं, उनमें से भी लाखों लोगों के नाम कटने की संभावना है । एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 40 से पचास हजार मतदाताओं के नाम के आगे "not recommended" लिखा है।

प्रश्न यह भी है कि जिन व्यक्तियों के नाम प्रारंभ से मतदाता सूचियों में रहे हैं, वे सभी मताधिकार का उपयोग करते रहे हैं। यदि ये सब अवैध थे तो क्या इनके आधार पर चुनी गई केंद्र और राज्य सरकारें अवैध और असंवैधानिक घोषित की जाएंगी? अब, एस आई आर के नाम पर नागरिकों से अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहना अथवा उसकी आड़ में दस्तावेज मांगना किसी भी रूप में औचित्य पूर्ण नहीं लगता है। वैसे भी जिन दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग ने नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी है, उनसे कैसे नागरिकता सिद्ध होती है, यह चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है, उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाता है। मजे की बात यह है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता । इसी प्रकार लाखों, करोड़ों लोग जो सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी में थे या हैं उनसे भी नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं मांगा गया। सबके द्वारा केवल इस बारे में स्व-घोषणा की गई कि वे भारतीय है, और उसी आधार पर उन्हें भारतीय मान लिया गया।

‘आधार’ को भी 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है जबकि अब लगभग सभी सरकारी कार्यों के लिए ‘आधार’ को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका कारण निर्वाचन आयोग द्वारा यह बताया जा रहा है कि कई लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे हैं । चुनाव आयोग ने यह किस प्रकार मान लिया कि अब जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा चाहे जा रहे हैं, वे उसी तरह फर्जी नहीं बनवाए जा सकते हैं? जिस देश में डिग्रियां तक विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी बनाई जा रही हों, वहां जन्म प्रमाण पत्र (स्वयम का या माता-पिता का) फर्जी बनाने में क्या बड़ी बात है? यदि ऐसा हुआ तो निर्वाचन आयोग की सारी प्रक्रिया का अर्थ ही क्या रह जाएगा?

निर्वाचन आयोग यह तर्क दे सकता है कि किसी को आपत्ति होने पर वह प्रमाण सहित अपील, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । सामाजिक संगठनों को यह कार्य करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि निर्वाचन आयोग ने जिन व्यक्तियों के नाम काट दिए हैं, उनकी श्रेणी वार सूची सावजनिक नहीं की गई है। अत: उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सकता है। पुरानी और नई सूचियों का मिलान करके भी ऐसी जानकारी निकालना लगभग असंभव है, क्योंकि बिहार में बूथों की संख्या 73000 से बढ़ा कर 92000 कर दी गई है।

यदि वास्तव में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है और किसी वर्ग विशेष को मतदान अधिकार से वंचित करने का उद्देश्य नहीं है, तो फिर निर्वाचन आयोग को उन सभी लोगों की सूची जारी करनी चाहिए जिनके नाम जून, 2025 की मतदाता सूची में से हटा दिए गए हैं। ऐसा न करके, निर्वाचन आयोग ने अनावश्यक आशंकाओं को जन्म दिया है।

यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में अपनाई जाएगी, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जा रहा है, तो संभावना है कि देश के 100 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 10 करोड़ से अधिक मतदाता, मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसका तो यही अर्थ होगा कि वयस्क होने के बाद भी वे भारत के किसी भी स्थान पर मत देने के योग्य नहीं माने जाएंगे । इतनी बड़ी संख्या किसी भी चुनाव में जीत हार के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। सामान्यतया, हार-जीत में अंतर 2-3% का होता है। 10% से अधिक मतदाताओं के नाम कम होने से चुनाव का फैसला पूरी तरह उलट सकता है।

इतनी सारी आशंकाओं को देखते हुए सभी विपक्षी दलों ने संसद में इस पर चर्चा करने के लिए एवं सड़क पर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। इस बारे में चुनाव आयोग ने यदि स्वयं ने निर्णय नहीं लिया एवं सर्वोच्च न्यायालय ने भी एस आई आर की इस प्रक्रिया को नहीं रोका, तो देश में लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका हो जाएगी। देश को इस समय निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया गया है, जहां एस आई आर पर लड़ाई आर पार की होने वाली है। फिलहाल, सबकी निगाहें सर्वोच्च न्यायालय में 12-13 अगस्त, 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी है।

—**अतिथि सम्पादक,**
राजेन्द्र भागवानत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



मदन राठौड़, भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष

भारत ने बीते दो दशकों में आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि सता में कौन था। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार की नरम, दुलमुल और तुष्टिकरण की नीति ने देश को बार-बार लहलुहान किया। मुंबई का 26/11 हमला जिसमें 166 निर्दोष नागरिक मारे गए, 2005 के दिल्ली धमाकों में 62 लोग मारे गए, 2008 में जयपुर में 63 और अहमदाबाद में 56 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, उन मासूमों की कुर्बानी की कहानियाँ हैं जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे उस वक़्त उस जगह पर थे।

और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि ऐसी कितनी ही अनगिनत आतंकी घटनाएँ आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से को लहलुहान करती रहती थीं, जिनसे हर भारतीय के मन में डर और असुरक्षा का भाव गहराता चला गया। यूपीए के दौर में पूरे देश के नागरिकों के मन में हर वक़्त यह डर बैठा रहता था कि न जाने कब और कहाँ धमाका हो जाए, कितने निर्दोष मर जाएँ।

सबसे शर्मनाक और दुःखद पहलू यह था कि उस समय बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आंसू बहाए, लेकिन क्या उन्होंने कभी दिल्ली, मुंबई, जयपुर या अहमदाबाद की सड़कों पर मारे गए निर्दोष नागरिकों के लिए आंसू बहाए? क्या कभी उन सैकड़ों घरों के जउड़ने का दर्द महसूस किया? यही यूपीए की नीति का असली चेहरा था – आतंकवादियों के लिए सहानुभूति और आम भारतीयों के जीवन के प्रति बेरुखी, जिसने पूरे देश का मनोबल गिराया और पाकिस्तान जैसे आतंक के प्रायोजक देश का हौसला बढ़ाया।

आज सोचिए, अगर मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद के उन भीषण हमलों के बाद उसी वक़्त ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाही की गई होती, तो शायद पाकिस्तान को उसी समय सबक

मिल गया होता और आतंकवाद की कमर टूट जाती। लेकिन सत्ता में रही कांग्रेस की नीति हमेशा आतंकवादियों के प्रति नरम रही, पाकिस्तान प्रेम इनके भीतर गहराई तक बैठा रहा, और इसी कारण देश बार-बार लहलुहान हुआ।

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति ही बदल दी गई। पहले हमला, फिर जवाब की बजाय घर में घुसकर जवाब देने की नीति आई। उरी हमले के बाद 2016 में सजिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, पुलवामा हमले के बाद 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक कर पाकिस्तान की धरती पर जैश-ए-मोहम्मद के अड्डों को नष्ट किया गया, और हाल ही में 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के नौ कैपों को मिट्टी में मिला दिया गया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया। आज पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहा है कि हमें मारा गया, लेकिन इधर भारत में कुछ लोग, कांग्रेस के नेता, ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियाँ छूछ रहे हैं, हमारे कितने विमान गिरे? कितना नुकसान हुआ?

और जब भी भारत मजबूती से

जवाब देता है, तभी कांग्रेस के नेता राष्ट्रविरोधी बयानों की झड़ी लगाकर देश की आवाज़ को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, सेना के साहस पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। यही कांग्रेस का चाल, चलन और चरित्र हमेशा से रहा है आतंकवादियों के लिए नरम दिल, पाकिस्तान के लिए सहानुभूति और भारत के सुरक्षा बलों पर सवाल। यूपीए के समय गुड मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद जिनके हाथ में थे, उनकी नीति कैसी रही होगी, यह उनके हाल के बयानों से

—**मदन राठौड़,**
प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान

मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव परवान पर

मेड़ता सिटी, (निंसां)। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव परवान पर है। मीरा जयंती महोत्सव समिति अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, सचिव रवि प्रकाश कमेडिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र बिड़ला सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। इस दौरान विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

मंदिर में मीरा बाई और ठाकुरजी की रजत रेवाड़ी के समक्ष विभिन्न समाज भजन मंडलियों द्वारा लगातार भजन कीर्तन किया जा रहा है। मीरा स्मारक राव दुदागढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार रात्रि में श्रीकिशन देव छतरी महंत हरिनायण दाम् पंथी के सानिध्य में मीरा स्मारक में भक्ति संंध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गौ ऋषि संत प्रकाशदास महाराज ने भजनों का गायन किया। मीडिया प्रभारी सुनील पुरी ने बताया कि इस दौरान संत प्रकाशदासजी ने गुरु भजनों के साथ भजन संंध्या शुरू की जिसमें



मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव में संतप्रकाशदास ने भजनों की प्रस्तुति दी।

पालिकाध्यक्ष शोभा लाहोटी, संत धीरज्राम पुष्कर रामस्नेही, साखी वीरेंद्र बाई सा आदि मौजूद रहे। इस दौरान संत प्रकाशदासजी ने गुरु भजनों के साथ भजन संंध्या शुरू की जिसमें

मीरा बाई, भगवान शिवजी, कृष्ण-राधा सहित अनेक देवी-देवताओं के भजनों का गायन किया। अनेक भक्ति मय, हास्य, व्यंग्य भजनों के माध्यम उपस्थित जन समुदाय को नाचने को मजबूर कर

दिया। संत प्रकाशदासजी ने अपने उद्बोधन से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। उन्होंने देश की सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्य को आमजन को

जैसलमेर में गिद्ध पक्षी पर जी.पी.एस. ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ

जैसलमेर, (निंसां)। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटीट्यूट ऑफ़ इंडिया और राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से थार के रेप्टर इकोलॉजी (शिकारी पक्षियों का परिस्थितिकी तंत्र) पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। “रेप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” नाम से शुरू हुआ शिकारी पक्षियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट जैसलमेर में जारी है और हाल ही में एक इजिप्शियन वल्चर और एक टॉनी ईगल पर ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ है।

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया देहरादून के वैज्ञानिक वरुण खेर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य थार क्षेत्र में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों जैसे बाज, मृत पशुओं को खाने वाले गिद्धों (स्कैवेंजर वल्चर-मृत भक्षी गिद्ध) की पारिस्थितिकी को समझना है। इस रिसर्च के तहत पहली बार थार क्षेत्र में रेप्टर प्रजातियों पर जीपीएस ट्रांसमीटर आधारित टेलीमेट्री अध्ययन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर का डेजर्ट

- “रेप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” नाम से शुरू हुआ शिकारी पक्षियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट जैसलमेर में जारी है**
- हाल ही में एक इजिप्शियन वल्चर और एक टॉनी ईगल पर ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ है**

नेशनल पार्क रेप्टर पक्षियों के लिए देश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां इनकी संख्या देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अध्ययन

इन प्रजातियों की आवाजाही, निवास स्थान, प्रजनन व्यवहार और खतरों को समझने में मदद करेगा।

जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु

उद्यान (डेजर्ट नेशनल पार्क) गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए काफी खास है। यहां भारत में पाए जाने वाले नौ गिद्धों की प्रजाति में आठ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी पर नजर रखते हुए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने राजस्थान वन विभाग की सहताया से इन शिकारी पक्षियों पर अध्ययन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिसका नाम “रेप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” रखा गया है।

गणेश महोत्सव के लिये इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई

भीलवाड़ा, (निंसां)। धर्म एवं समाज सेवा के लिए समर्पित श्रीगणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान आगामी 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की समरसता 27 अगस्त से शुरू होगी। समिति द्वारा इंदौर के मूर्तिकारों ने भगवान गणपति की आकर्षक मल्टी कलर प्रतिमाएं

स्थानीय स्तर पर तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। समिति के मीडिया प्रभारी महावीर समदानी के अनुसार गत 30 वर्षों से गणेश महोत्सव मना रही समिति के द्वारा हर वर्ष भगवान गणपति की मूर्ति स्थानीय मांग के अनुसार तैयार की गई जाती है। इस बार 10 दिवसीय

आयोजन 27 अगस्त गणेश चतुर्थी बुधवार से छह सितंबर शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन विजयन के साथ संपन्न होगा। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की जिसका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय

भावना को बढ़ावा देना था। उन्होंने गणेश उत्सव को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जहां देश भक्ति के गीत गाए जाते थे। राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया जाता था। गणेश महोत्सव के तहत सभी जातियों, धर्मों और समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाना है। ऐसे उत्सवों से राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवादी

भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के माध्यम से ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का मंच बनता जा रहा है। इस तथ्यैभर को एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहां लोग अपनी संस्कृति और हेरिटेज को मना सके।

राशिफल मंगलवार 5 अगस्त, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 11:23 तक, ऐन्द्रयन योग प्रातः 7:24 तक, विष्टि करण दिन 1:13 तक, चन्द्रमा आज दिन 11:23 से धनु राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज रवियोग दिन 11:23 तक है। कुमार योग दिन 11:23 से दिन 1:13 तक है। आज पवित्र एकादशी व्रत, मंगला गौरी पूजन है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:15 से 10:54 तक, लाभ-अमृत 10:54 से 2:12 तक, शुभ 3:51 से 5:29 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 7:08

मे़ष	सिंह
	
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक परेशानियों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है।दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
वृष	कन्या
	
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है।दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।	आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।
मिथुन	तुला
	
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।दिनचर्या में सुधार होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	आर्थिक कारणों से अटकें हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। संभावित ख़ाते से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित बातों सफल रहेगी।
कर्क	वृश्चिक
	
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।	व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु	मकर
	
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।	आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।
कुंभ	मीन
	
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटकें हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में शुभ-मार्गालिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

लालसोट में ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना का सीएम भजनलाल ने किया शिलान्यास

हर गांव-ढाणी तक सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाना हमारा संकल्प : भजनलाल

दौसा/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के हर गांव, हर ढाणी और हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को सशक्त एवं समृद्ध बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र स्थित डूंगरपुर गांव में आयोजित समारोह में रिमोट का बटन दबाकर ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि महादेव की कृपा से प्रदेश में भरपूर बारिश से जलाशय लबालब हो गए हैं और ईसरदा बांध में भी खूब पानी आया है। उन्होंने कहा कि ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना के तहत लालसोट में लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत से 8 स्वच्छ जलाशयों, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 280 किलोमीटर राईजिंग मुख्य पाइप लाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइप लाइन एवं 1360 किलोमीटर वीडोएस पाइप लाइन बिछाई जाएगी।



सीएम भजनलाल शर्मा ने बटन दबाकर ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों से 302 गांवों की लगभग 5 लाख 58 हजार आबादी और लालसोट की करीब 69 हजार आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। शर्मा ने कहा कि लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य विकास कार्यों की भी स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लालसोट

विधानसभा के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान कर संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएच-24 से एनएच-11 एई वाया नांगल मोड़, देवली रोड-लालसोट बाईपास के नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण हेतु कार्यदिश जारी किए जा चुके हैं। एनएच 148 डूंगरपुर मोड़ से डोब बाया हरिपुरा एवं लालसोट से खटवा तक सड़क नवीनीकरण एवं

चौड़ाईकरण कार्य करवाया जा रहा है। लालसोट नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही श्यामपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एवं कन्या महाविद्यालय, लालसोट को पीजी में क्रमोन्नत किया गया है।

समारोह में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ ‘ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से लगभग 6.27 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा’

के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उच्च किस्म के खाद-बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने दौसा क्षेत्र में ईसरदा बांध का पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ जिससे इसके कार्य समय पर पूरे नहीं हुए। अब हमारी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंदूर का पौधा भी लगाया।

2.16 करोड़ का डोडा-पोस्ट जब्त्, आरोपी गिरफ्तार

नागौर, (निर्सं)। नागौर पुलिस ने जिला स्तरीय अभियान ऑपरेशन नीलकंठ के तहत एक खेत में दबिश देकर 1441 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्ट जब्त् किया है। अंतर्गोष्ठी बाजार में बरामद डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए है। सयुक्त कार्रवाई में पांचौड़ी थाना, सदर और नागौर डीएसटी टीम शामिल रही।

नागौर एसपी मधुल कच्छवा ने बताया कि नशे व मादक पदार्थों के खिलाफ नागौर जिला स्तर पर ऑपरेशन

नीलकंठ चलाया जा रहा है। सूचना मिली कि भेड़ गांव का श्रवणराम बिश्नोई (40) खेत में अवैध डोडा-पोस्ट छिपा रहा है सूचना की पुष्टि होते ही स्थानीय पांचौड़ी थाना टीम को अवगत कराया गया। टीम ने आरोपी श्रवणराम के खेत पर छापा मारा। पुलिस ने वहां से 50 कट्टों में भरा 1441 किलो डोडा-पोस्ट बरामद किया और मौके से ही आरोपी श्रवण राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

सातवीं मंजिल से नीचे गिरा बालक, मौत

कोटा, (निर्सं)। बोरखेड़ा थाना इलाके में खेलते समय पैर फिसलने से सातवीं मंजिल की सीढ़ियों से नीचे गिरने से बालक की मौत हो गई। 12 वर्षीय बालक हर्ष प्रधान अपार्टमेंट की छत पर खेलते समय पैर फिसलने से सीढ़ियों पर आ गया और सीधे नीचे फ्लोर पर गिर गया। जिसे अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बोरखेड़ा थानाधिकारी

देवेश भारद्वाज ने बताया कि मृतक बालक हर्ष प्रयाग उड़ीसा का निवासी है जो परिवार वालों के साथ कोटा में कुछ ही महीने पहले आया था। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक बालक हर्ष की मां इलाके के कोरल पार्क स्थित श्याम अपार्टमेंट में वाईन का काम करती है। बालक अपार्टमेंट की छत पर खेल रहा था, पैर फिसलन से बालक सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ गया।

पावटा, (निर्सं)। तेज रफ्तार डंपर ने एक महिला को कुचला दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और सड़क मार्ग जाम कर दिया।

■ आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया

■ मुवावजा देने के आश्वासन के बाद चार घंटे बाद धरना समाप्त हुआ

प्रागपुरा थाना क्षेत्र के बुचारा निवासी लक्ष्मी देवी (48) पत्नी प्रहलाद सोमवार की सुबह घर से अपने भाई के लड़के अजय के साथ बाइक पर पावटा डाक्टर के दिखार कर दवाई लेकर वापस बुचारा आ रही थीं। उसी समय समय ग्राम बुचारा पहुंचने पर कालीबाय के पास क्रशर के डंपर ने



हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

महिला को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। सुबह करीब 12 बजे हुई इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

आसपास के ग्रामीण और परिजन दौड़कर मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी लगते ही डंपर चालक तो मौके से भाग गया। आसपास के लोगों से सूचना गांव पहुंची, तो देखते ही

देखते लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। महिला के मौत की खबर सुनते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मार्ग को जाम कर मृत महिला के शव को लेकर धरने पर बैठ गए व क्रेशर व डंपर मालिक को मौके पर बुलाने व क्षेत्र में इन वाहनों की वजह से घंटित हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने

रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

उदयपुर, (निर्सं)। पति की मदद के लिए परिवारदिया के सहयोगी से एक हजार रुपये रिश्त लेते गोवर्धन विलास पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनन्त कुमार ने बताया कि 4 अगस्त को परिवारदिया लक्ष्मीबाई निवासी काया ने सहपरिवारी भगवान निवासी काया के साथ ब्यूरो कार्यालय उदयपुर में एक

■ थाने में मारपीट नहीं करने एवं जमानत में मदद करने के एवज में दो हजार रुपये रिश्त मांगी

रिपोर्ट दी। उसने बताया कि गोवर्धन विलास पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीणा जो एक्सआईएक्ट मामले में बंदी मेरे पति होमा के साथ थाने में मारपीट नहीं करने एवं जमानत में मदद करने के एवज में 2 हजार रुपये रिश्त की मांग कर रहा है। जिसका सत्यापन कराया तो हेडकांस्टेबल संजय कुमार ने 1500 रुपये की रिश्त उसी समय ले ली। शेष नकदी कोर्ट में परिवारजन से उपलब्ध करवाने के लिए कहा। सत्यापन होने पर एसीबी के पुलिस निरीक्षण नरपतिसिंह मय टीम ने संजय मीणा को कोर्ट परिसर में परिवारी से 1000 हजार रुपये रिश्त लेते रहे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की टीम आरोपी के मकान की तलाश कर रही है।

बीस हजार की रिश्त लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

उदयपुर, (निर्सं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलिजेंस उदयपुर की टीम ने लूट के मामले में आरोपी नहीं बनाने तथा जब्त कार छोड़ने के एवज में पुलिस के हेडकांस्टेबल को बीस हजार रुपये रिश्त लेते गिरफ्तार किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अगस्त को पीड़ित यशपालसिंह चौहान निवासी कल्ला, खेड़ी विरान पोस्ट गुंजोल नाथद्वारा राजसमंद ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलीजेंस यूनिट उदयपुर को रिपोर्ट दी। जिसमें उसने बताया कि मुझे खमनोर पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में लूट के मामले में आरोपी नहीं बनाने एवं जब्तशुदा कार को छोड़ने के एवज में थानाधिकारी खमनोर शैतानसिंह नाथावत के रीडर कृष्णकुमार पुत्र सरदाराराम निवासी मोटूका तहसील नीमकाथाना थाना सीकर हॉल हेडकांस्टेबल पुलिस थाना खमनोर 26 हजार रुपये रिश्त की मांग कर रहा है। पूर्व में मुझसे डरा धमकाकर 35 हजार रुपये वसूल कर चुका है।

जिस पर एक अगस्त को शिकायत

■ लूट के मामले में आरोपी नहीं बनाने तथा जब्त कार छोड़ने के एवज में रिश्त ली

का सत्यापन किया तो रीडर हेडकांस्टेबल द्वारा थानेदार के नाम से रिश्त मांगने की पुष्टि की गई। इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रहलादसिंह कृष्णाय के सुपरवाजन में ब्यूरो टीम की प्रभारी निरीक्षक डॉ. सोनु शेखावत के नेतृत्व में एएसआई मुनीर मोहम्मद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी दलपतसिंह, कांस्टेबलन अजय कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलीजेंस यूनिट कनिष्ठ सहायक लक्ष्मणसिंह टीम ने सोमवार को थानाधिकारी के नाम पर हेड कांस्टेबल कृष्णा कुमार को 20 हजार रुपये रिश्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की टीम मामले में खमनोर थानाधिकारी की संदर्भ भूमिका के मामले में जांच कर रही है।

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर ई-निविदा 04/2025-26 कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर तथा कृषि अनुसंधान उपकेंद्र, सुमेरपुर में श्रमिकों की आपूर्ति करने हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एवं जानकारी www.sppp.raajasthan.gov.in एवं eproc.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। UBN No. : JAU2526SLRC00071 Eproc ID: 2025_AGUJD_492103_1 हल.बज.र/री/25/1470	निबंध (विा)
--	---------------------------

Government of Rajasthan Water Resources Department Office of the Executive Engineer Water Resources Division Dholpur Tel & Fax No. 05642-220880 E-mail- eeurddholpur1@gmail.com E-NIT NO. 06 YEAR 2025-26	Date-25.07.2025 On behalf of government of Rajasthan NIT No. 06 Year 2025-26 is invited from eligible contractor for 04 Nos. works cost of works is Rs. 66.41 Lacs. The detail of works is available on following websites. UBN No. (1) WRD2526GLOB00768, (2) WRD2526GLOB00769, (3) WRD2526GLOB00770, (4) WRD2526GLOB00771 1. www.dinrajasthan.gov.in 2. www.sppp.raajasthan.gov.in
--	---

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DIVISION, JHALAWAR E-NIT NO. 05/2025-26 On Behalf of The Governor of Rajasthan, e-tender is invited from interested bidders for the work for 1. Plantation work (ERCP) Mission Haryana Rajasthan water resources Division Jhalawar Tehsil Jhalapatan, Bakani, Pachphar. (Est. Cost Rs. 39.25 Lac) 2. Plantation work (ERCP) Mission Haryana Rajasthan water resources Division Jhalawar Tehsil Khanpur. (Est. Cost Rs. 39.25 Lac) for Completion period of 03 Months (Including Rainy Season) from 26.07.2025 (9.30 AM) to 06.08.2025 (06.00 PM). Other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal www.eproc.raajasthan.gov.in, www.dipr.raajasthan.gov.in, sppp.raajasthan.gov.in or www.watersources.raajasthan.gov.in NIS CODE- WRD2526A0302, UBN For Item No. 01-WRD2526WSOB00796, UBN For Item No. 02-WRD2526WSOB00797	(Pankaj Singh) Executive Engineer Water Resources Division, Jhalawar
---	---

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर विज्ञापित	दिनांक-28.07.2025 आयोग के वि. सं. 09/2024-25 दिनांक 05.08.2024 द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASSISTANT STATISTICAL OFFICER) के कुल 43 (एक अनुसूचित क्षेत्र-31 एवं अनुसूचित क्षेत्र-12) पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पर आमंत्रित किये गये थे। विभागा द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु दिनांक 30.07.2025 से दिनांक 13.08.2025 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पर पुनः आमंत्रित किये जाते हैं। इसके पश्चात रिक निष्पत्ति हो जाएगा। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpcc.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ.(SSO) पोर्टल https://sso.raajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। विभाग से प्राप्त संशोधित वकीला वकीलपत्र एवं अन्य सूचना के संबंध में आयोग की वेब-साइट पर जारी शुद्धि पत्र संख्या 6/2025-26 का अभ्यर्थी अवलोकन कर सकते हैं। DIPR/C/10916/2025
---	---

राज्य सरकार ने 103 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किये

बीकानेर, (निर्सं)। राज्य सरकार ने 24 घंटे में 612 शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिया। इनमें प्रिंसिपल के साथ ही ब्लॉक लेवल से स्टेट के अधिकारी भी शामिल हैं। पहली लिस्ट रविवार को 509 प्रिंसिपल की जारी हुई थी। इसके बाद सोमवार सुबह पहले 35 और फिर 68 शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। जून 2023 के बाद से शिक्षा विभाग में ट्रांसफर नहीं हुए थे। इनमें कई ऐसे भी थे, जो कांग्रेस सरकार में लगे हुए थे। इधर, इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर से रोक हटाने

और 10 हजार टीचर के ट्रांसफर का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। हालांकि सरकार ने इसे खारिज कर पूरा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। प्रिंसिपल ट्रांसफर की एक और लिस्ट सोमवार सुबह जारी की गई। इस लिस्ट पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-साइन देर रात तीन बजे हुए हैं। ये लिस्ट सोमवार अल सुबह सार्वजनिक हुई। इसमें 35 प्रिंसिपल को पोस्टिंग दी गई है। इसमें 23 प्रिंसिपल वे हैं, जिन्हें अलग-अलग कारणों से एपीओ किया गया था। वहीं चार प्रिंसिपल का ट्रांसफर

संशोधित किया गया है। इन्हें स्कूल से स्कूल में ही लगाया गया है। इसमें बीकानेर के महारानी स्कूल की प्रिंसिपल शारदा पहाड़िया भी शामिल हैं। जिन्हें पहले देशनोक लगाया गया था, लेकिन अब बीकानेर शहर में ही उसकी की बारी स्कूल में प्रिंसिपल लगाया गया है। इसके बाद तीसरी लिस्ट सुबह साढ़े छह बजे जारी हुई है। इसमें बीकानेर और अजमेर के राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान (टीटी कॉलेज) में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल और लेक्चरर लगाए गए हैं।

बिजली का पोल गिरने से बुजुर्ग की मौत

टोंक, (निर्सं)। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा कुआं, पोली हवेली के पास रविवार को पेड़ काटते समय पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से बिजली पोल टूट कर नीचे किराना दुकान पर खड़े बुजुर्ग के सिर पर गिर गया, जिससे बुजुर्ग का सिर फटने से उसकी मौत हो गई।

थाना कोतवाली प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि पोली हवेली निवासी अवरार अहमद (72) जो किराने की दुकान पर घरेलू सामान लेने गया था, तभी दुकान के पास काटा जा पेड़ बिजली की लाइन के तार जर्जर

पड़े बिजली के पोल आ गिरा तभी पोल टूटकर अवरार अहमद के सिर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट गया। जिसे परिजनों और मोहल्लेबासियों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराकर घटना में बिजली निगम की लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां परिजनों ने मुआवजा देने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पर लिखकर परिवारी को बताया, परन्तु परिवारी ने सभापति से कहा कि मैं 30 हजार रुपये ही दूंगा। इस पर सभापति ने आकाश कनिष्ठ सहायक से मिलने के लिये कहा। परिवारी आरोपी आकाश कलौसिया से मिला तो उसने कहा कि मेरे पास सभापति का कॉल आया था, उन्होंने 40 हजार रुपये की कहा है, मैं सभापति संजय शुक्ला से पूछकर ऊनके बताया अनुसार व्यक्ति को रुपये दिलाऊंगा। रिश्त की मांग का सत्यापन होने के पश्चात एसीबी झालावाड़ द्वारा सोमवार को ट्रेप कार्यवाही कर संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ के बताया अनुसार आकाश कलौसिया कनिष्ठ सहायक ने अजय कुमार मारवाड़ा टैन्ट हाउस को 30 टीमां हजार रुपये रिश्त राशि दिलावाई, जिस पर अजय कुमार प्राइवेट व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के घर की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा।

तीस हजार की रिश्त लेते झालावाड़ नगर परिषद का बाबू व दलाल गिरफ्तार

झालावाड़, (निर्सं)। झालावाड़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विरुद्ध द्वारा नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला भी आरोपी बनाए गए हैं। वहीं नगर परिषद के बाबू आकाश कलौसिया एवं दलाल अजय को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी झालावाड़ की एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की झालावाड़ चौकी द्वारा कार्रवाई करते हुये संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ के कहने पर आकाश कलौसिया कनिष्ठ सहायक एवं अजय कुमार प्राइवेट व्यक्ति को परिवारी से 30 हजार रुपये रिश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।



एसीबी टीम ने नगर परिषद झालावाड़ का बाबू व दलाल को रिश्त लेते हुए गिरफ्तार किया।

करके शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। एडिशनल एसपी ने बताया कि परिवारी द्वारा गत 21 जुलाई को शिकायत दी गई कि, प्राथी की गांव मुण्डेरी में भूमि स्थित है, जिसका खसरा नम्बर 380 है। जमीन को पर्यटन ईकाई भवन (मोटेल) में

कन्वर्जन हेतु पट्टे की फाईल नगर परिषद झालावाड़ में गत 4 वर्षों से पेंडिंग पड़ी है। जिसकी पॉपर ऑफ गांव में नशे नाम है, जिसकी 90ए की कार्यवाही सहित आयुक्त के हस्ताक्षर होकर समस्त राशि जमा करवा रखी है। जिस पर पट्टा जारी

■ मामले में आरोपी परिषद सभापति संजय शुक्ला फरार, एसीबी टीम तलाश में लगी हुई है

■ पट्टा जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिये 50 हजार रुपये की मांग की

करने के लिये सभापति संजय शुक्ला के हस्ताक्षर होना शेष है। उक्त फाईल पर हस्ताक्षर के लिये परिवारी सभापति संजय शुक्ला से मिला तो उन्होंने हस्ताक्षर करने के लिये 50 हजार रुपये की मांग की। शिकायत पर रिश्त मांग का सत्यापन करवाने पर परिवारी के अनुग्रह पर आरोपी संजय शुक्ला सभापति द्वारा 40 हजार रुपये कागज

पर लिखकर परिवारी को बताया, परन्तु परिवारी ने सभापति से कहा कि मैं 30 हजार रुपये ही दूंगा। इस पर सभापति ने आकाश कनिष्ठ सहायक से मिलने के लिये कहा। परिवारी आरोपी आकाश कलौसिया से मिला तो उसने कहा कि मेरे पास सभापति का कॉल आया था, उन्होंने 40 हजार रुपये की कहा है, मैं सभापति संजय शुक्ला से पूछकर ऊनके बताया अनुसार व्यक्ति को रुपये दिलाऊंगा। रिश्त की मांग का सत्यापन होने के पश्चात एसीबी झालावाड़ द्वारा सोमवार को ट्रेप कार्यवाही कर संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ के बताया अनुसार आकाश कलौसिया कनिष्ठ सहायक ने अजय कुमार मारवाड़ा टैन्ट हाउस को 30 टीमां हजार रुपये रिश्त राशि दिलावाई, जिस पर अजय कुमार प्राइवेट व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के घर की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, निकट ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह), खनिज लाभकारीकरण, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह), खनिज लाभकारीकरण, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना जोकि, निकट ग्राम गढ़ तकनेट, तहमील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां) तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
- और चूंकि मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- उक्त परियोजना से सम्बंधित मंक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी मारांश) एवं संस्तिप कायपालक मार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
 - जिला कलक्टर, सीकर।
 - अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
 - राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
 - महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
 - उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर।
 - ग्राम पंचायत, गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - राजीव गाँधी मेसेवा केंद्र, ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एमएमओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 25.07.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.09.2025 (बुधवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामासी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

